गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 250
दि. 10.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

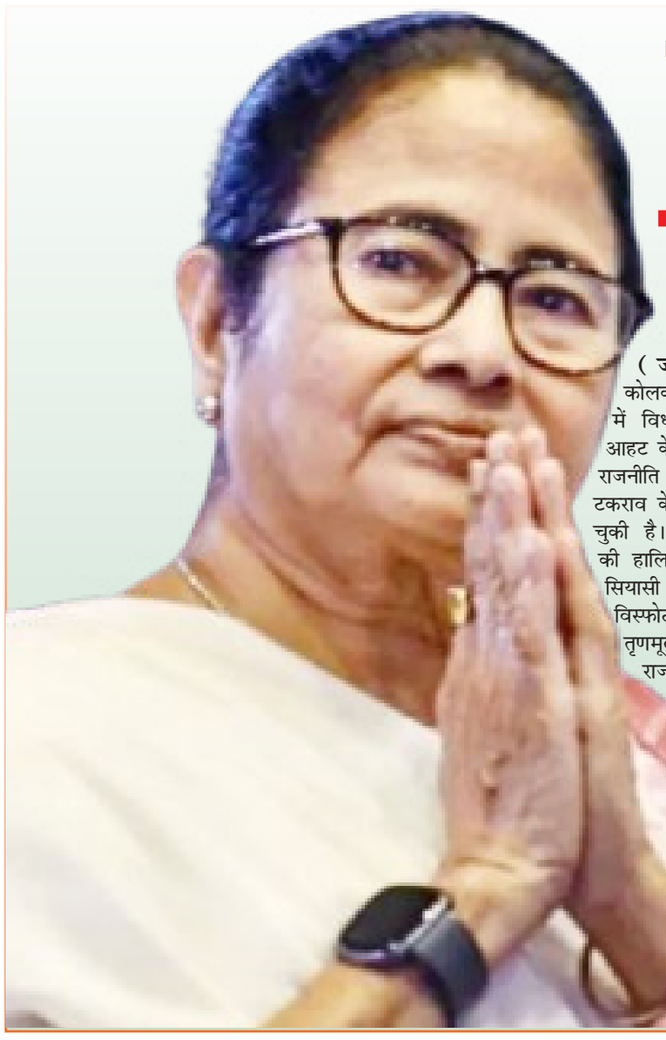

ईडी की छापेमारी पर ममता बनर्जी का खुला ऐलान, सड़कों से दिल्ली तक टकराव के संकेत

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राज्य की राजनीति एक बार फिर तीखे टकराव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय की हालिया कार्रवाई ने इस सियासी माहौल को और विस्फोटक बना दिया है। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े राजनीतिक सलाहकार संगठन आई-पैक के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे केंद्र सरकार की सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार देते हुए खुला मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कोलकाता की सड़कों पर उतरा उनका विरोध मार्च न केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया था, बल्कि यह संकेत भी था कि आने वाले दिनों में यह लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को डराने और कमजोर करने की कोशिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को बदनाम करना चाहती है। रैली के दौरान ममता बनर्जी के तेवर बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए कहा कि अगर उन पर और उनकी सरकार पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला गया तो वह कथित कोयला घोटाले से जुड़ा एक पेन ड्राइव सार्वजनिक कर देंगी, जिससे पूरे देश में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस पेन ड्राइव में ऐसे तथ्य और सबूत मौजूद हैं, जो दिल्ली तक बैठे बड़े नेताओं की भूमिका को उजागर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने संवैधानिक पद की गरिमा का सम्मान करते हुए अब तक चुप रही हैं, लेकिन अब चुप्पी तोड़ने का समय आ सकता है।

मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यह विरोध किसी एक एजेंसी के खिलाफ नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के अन्याय, अपमान और दमनकारी रवैये के खिलाफ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर हमला होता है, तो जनता का जवाब सड़क से ही आता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी की छापेमारी का असली उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों, गोपनीय दस्तावेजों और संगठनात्मक जानकारियों को जब्त करना था, ताकि चुनाव से पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सके। उन्होंने इसे एक गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी की चुनावी जानकारी को निशाना बनाया है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जाधवपुर के 8 बी बस स्टैंड से शुरू हुआ यह विरोध मार्च धीरे-धीरे एक विशाल जनसमूह में तब्दील होता गया। दक्षिण कोलकाता की सड़कों पर हजारों की संख्या में तृणमूल समर्थक जमा हो गए। हाथों में पार्टी के झंडे, पोस्टर और नारों के साथ लोग मुख्यमंत्री के पीछे-पीछे चलते नजर आए। पूरे मार्ग में केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी होती रही। सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को जनभावनाओं से जोड़ने में सफल हो रही है और इसे एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है।

शाम करीब साढ़े चार बजे जब यह मार्च हाजरा मोड़ पर पहुंचकर समाप्त हुआ, तब ममता बनर्जी ने एक बार फिर मंच से केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वह केंद्र के कथित दमन के खिलाफ चुप बैठने वाली नहीं हैं और जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर अदालत और संसद तक संघर्ष करेंगी। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता इस अपमान का जवाब सही समय पर देगी और लोकतंत्र की ताकत एक बार फिर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता डरने वाली नहीं है और वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

इस विरोध मार्च में तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास जैसे अनुभवी नेता, सांसद और अभिनेता देव, विधायक सोहम समेत पार्टी के अनेक सांसद, विधायक और सांस्कृतिक जगत से जुड़ी हस्तियां भी मुख्यमंत्री के साथ सड़कों पर उतरीं। उनकी मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट है और नेतृत्व के साथ खड़ी है। यह प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने का भी जरिया बना।

उल्लेखनीय है कि यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब एक ओर हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई है और दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। गुरुवार को आई-पैक प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और साल्ट लेक स्थित कार्यालय पर ईडी की कार्रवाई के बाद शुक्रवार सुबह ही मुख्यमंत्री ने साल्ट लेक कार्यालय के बाहर से विरोध मार्च की घोषणा कर दी थी। इस त्वरित प्रतिक्रिया ने यह दिखा दिया कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ईडी की इस कार्रवाई और ममता बनर्जी के तीखे विरोध ने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में बदल दिया है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज हो सकता है और इसका असर न सिर्फ पश्चिम बंगाल, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। चुनावी मौसम में यह मुद्दा कितना बड़ा रूप लेता है, यह आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल की सड़कों पर शुरू हुई यह सियासी जंग अब दिल्ली तक पहुंचने के संकेत दे रही है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच का रास्ता साफ, धामी सरकार ने उठाया बड़ा फैसला

(जीएनएस)। देहरादून। लंबे समय से चल रही राजनीतिक और सामाजिक उठापटक के बाद आखिरकार बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस संवेदनशील मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की भावनाओं और उनकी मांग का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इस फैसले के साथ ही राज्य में चल रहे धरना-प्रदर्शन और न्याय की मांग को लेकर उठ रही आवाजों को एक बड़ा जवाब माना जा रहा है। अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट में कार्यरत थीं। आरोप है कि रिसॉर्ट में उनसे एक विशेष व्यक्ति को 'विशेष सेवा' देने के लिए दबाव बनाया गया था। जब अंकिता ने इसका विरोध किया और इंकार कर दिया, तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह मामला सामने आते ही पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था और

इसे महिला सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर सवाल माना गया। निचली अदालत ने इस प्रकरण में रिसॉर्ट मालिक समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा के बावजूद यह मामला समय-समय पर नए सवालों और आरोपों के कारण चर्चा में बना रहा। हाल के दिनों में इस हत्याकांड से जुड़ी एक कथित ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें किसी वीआईपी के इस मामले में शामिल होने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो ने पूरे प्रकरण को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया और राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा गया। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इस आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग तेज कर दी और सीबीआई जांच की मांग को लेकर जगह-जगह धरना-प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी दबाव और अंकिता के परिजनों की मांग के बाद राज्य सरकार ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को लेकर एक वीडियो संदेश भी जारी किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार की अब तक की कार्रवाई का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिली, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई शुरू की। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस मामले में तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया और प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मामले की ठोस पैरवी की गई, जिसके चलते ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी।

सीएम धामी ने यह भी कहा कि एसआईटी की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने कभी किसी दबाव में आकर काम नहीं किया और न ही किसी को बचाने की कोशिश की। बावजूद इसके, यदि पीड़ित परिवार और समाज के एक वर्ग को अब भी संदेह या असंतोष है, तो सरकार उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीबीआई जांच की सिफारिश से एक ओर जहां सरकार पर लगे आरोपों को जवाब मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इस मामले से जुड़े हर पहलू की नए सिरे से पड़ताल हो सकेगी। यह फैसला अंकिता भंडारी के परिजनों के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण माना जा रहा है, जो लंबे समय से इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आने की मांग कर रहे हैं।

हाइपरसोनिक ताकत की दिशा में भारत की बड़ी छलांग, डीआरडीओ ने 12 मिनट तक सफल स्क्रैमजेट परीक्षण कर रचा इतिहास

(जीएनएस)। हैदराबाद। भारत ने अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए हाइपरसोनिक मिसाइल विकास की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने स्क्रैमजेट इंजन से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से साझा की है, जिसे देश की सामरिक क्षमता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, डीआरडीएल ने एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर का लंबी अवधि का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। इस परीक्षण की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि स्क्रैमजेट इंजन 12 मिनट से अधिक समय तक लगातार सक्रिय अवस्था में कार्य करता रहा। हाइपरसोनिक तकनीक के क्षेत्र में यह अवधि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि अत्यधिक गति पर इंजन को स्थिर और

नियंत्रित रखना सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती होती है। यह परीक्षण 9 जनवरी 2026 को स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट सुविधा में किया गया, जहां सभी मानकों पर यह प्रयोग सफल रहा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सफलता भारत को हाइपरसोनिक हथियारों की दौड़ में एक मजबूत स्थान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। हाइपरसोनिक मिसाइलें सामान्य मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक तेज होती हैं और इन्हें रोक पाना मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों के लिए बेहद कठिन होता है। ऐसे में स्क्रैमजेट तकनीक का सफल और दीर्घकालिक संचालन भारत की सामरिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला माना जा रहा है।

डीआरडीएल की यह उपलब्धि न केवल तकनीकी दक्षता को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भारत भविष्य के युद्ध परिदृश्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है।

स्क्रैमजेट इंजन को अत्याधुनिक जेट इंजन तकनीक का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यह इंजन पारंपरिक जेट इंजनों से पूरी तरह अलग होता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के घूमने वाले कम्प्रेसर या टर्बाइन की आवश्यकता नहीं होती। यह अत्यधिक तेज गति पर हवा को सीधे अंदर खींचता है और उसी हवा को संपीड़ित कर ईंधन के साथ जलाता है। इस प्रक्रिया में इंजन सुपरसोनिक अवस्था में ही दहन करता है, जिससे इसे स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट कहा जाता है। यही तकनीक मिसाइल या हवाई वाहन को ध्वनि की गति से पांच गुना या उससे भी अधिक तेज उड़ान भरने में सक्षम बनाती है।

हाइपरसोनिक गति पर उड़ान भरते समय इंजन और उसके आसपास का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे उपकरणों के पिघलने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। ऐसे में एक्टिव कूलिंग तकनीक के साथ स्क्रैमजेट इंजन को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। डीआरडीएल द्वारा 12 मिनट से अधिक समय तक इस इंजन का सफल संचालन यह दर्शाता है कि भारत ने इस जटिल समस्या का व्यावहारिक समाधान खोज लिया है। यह भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और उन्नत हवाई प्लेटफॉर्म के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीकी सफलता से भारत की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली को नई गति मिलेगी। आने वाले वर्षों में यह तकनीक न केवल मिसाइलों, बल्कि अंतरिक्ष और पुनः उपयोग योग्य प्रक्षेपण वाहनों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वैश्विक स्तर पर केवल गिने-चुने देश ही हाइपरसोनिक तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति कर पाए हैं और अब भारत का नाम भी इस विशिष्ट श्रेणी में शामिल होता नजर आ रहा है।

कर्नाटक की सियासत में बयानबाजी तेज, गृह मंत्री परमेश्वर ने उपमुख्यमंत्री के दखल के आरोपों को नकारा

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। इस बार मुद्दा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कथित हस्तक्षेप को लेकर उठा है, जिस पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने साफ शब्दों में स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री द्वारा गृह विभाग के कामकाज में किसी तरह का दखल नहीं दिया गया है और इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। परमेश्वर जेडी (एस) नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की उन टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे, जिनमें उन्होंने डीके शिवकुमार पर गृह विभाग के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। दरअसल, हाल ही में बल्लारी में हुई झड़पों के बाद उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार वहां पहुंचे थे और पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी। इसी को लेकर एचडी कुमारस्वामी ने सवाल उठाया था कि शिवकुमार किस हैसियत और किसकी अनुमति से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने यह भी कहा था कि गृह विभाग की जिम्मेदारी किसी और मंत्री के पास है, ऐसे में उपमुख्यमंत्री का इस तरह हस्तक्षेप करना संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। इन आरोपों के बाद कर्नाटक की सियासत में हलचल मच गई और कांग्रेस सरकार के भीतर अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि डीके शिवकुमार एक जिम्मेदार नेता हैं और उपमुख्यमंत्री होने के साथ-साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि संविधान के अनुसार उपमुख्यमंत्री के पास कोई अतिरिक्त या विशेष अधिकार नहीं होते और वह भी अन्य मंत्रियों की तरह ही होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी संवेदनशील स्थिति में उनका मौके पर जाना गलत है। परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि जिस समय बल्लारी की घटना हुई, वह स्वयं वहां नहीं जा सके थे, ऐसे में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर उपमुख्यमंत्री का वहां जाना पूरी तरह उचित था।

सबरीमाला में सोना चोरी मामले ने लिया बड़ा मोड़, अयप्पा मंदिर के मुख्य पुजारी गिरफ्तार, ईडी भी जांच में कूदी

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर से जुड़े सोना चोरी मामले में शुक्रवार को उस समय बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ गया, जब विशेष जांच दल ने मंदिर के मुख्य पुजारी कंदरारू राजीव को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने न सिर्फ राज्य की धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है, बल्कि देशभर में इस संवेदनशील मामले को लेकर नई बहस भी छेड़ दी है। वहीं दूसरी ओर, इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है, जिससे जांच का दायरा और गहराता नजर आ रहा है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को एसआईटी ने कंदरारू राजीव को हिरासत में लेने के बाद पहले एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर उनसे गहन पूछताछ की। इसके बाद उन्हें एसआईटी टीम कार्यालय लाया गया, जहां औपचारिक रूप से उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। यह गिरफ्तारी उस मामले में हुई है, जिसे सबरीमाला मंदिर की पवित्रता और विश्वास से जुड़ा बेहद संवेदनशील प्रकरण माना जा रहा है। मंदिर से जुड़े सोने की कथित हेराफेरी और चोरी के आरोपों ने पहले ही राज्य में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर रखी है। एसआईटी अधिकारियों का कहना है कि मुख्य पुजारी की गिरफ्तारी मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पद्मकुमार के बयानों के आधार पर की गई है। जांच में सामने आया है कि कंदरारू राजीव के पोट्टी के साथ करीबी संबंध थे और उन्होंने मंदिर में द्वारपालक यानी रक्षक देवता की प्लेटों और श्रीकोविल, यानी गर्भगृह के द्वार-फ्रेम की री-प्लेटिंग की सिफारिश की थी। जांच एजेंसी का मानना है कि इसी प्रक्रिया के दौरान सोने की हेराफेरी की साजिश रची गई और इसमें कई स्तरों पर मिलीभगत हुई। एसआईटी के अनुसार, जब त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने री-प्लेटिंग के कार्य के लिए मुख्य पुजारी से अनुमति मांगी थी, तब कंदरारू राजीव ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। जांच अधिकारियों का दावा है कि इस निर्णय के पीछे केवल धार्मिक या तकनीकी कारण नहीं थे, बल्कि इसमें आपराधिक साजिश और लाभ पहुंचाने की मंशा भी शामिल थी। यही कारण है कि एसआईटी ने पहले उनसे कई दौर की पूछताछ की थी और सबूतों के आधार पर अब गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

संपादकीय

सर्दी, स्नान और सरकारी आत्मा का वैज्ञानिक विद्रोह

मित्रो! संसार चाहे कुछ भी कहे, मौसम विज्ञानी चाहे जितने ग्राफ बना लें, डॉक्टर चाहे कितनी ही डिग्रियां दीवार पर टांग लें, पर सर्दियों में नहाने को लेकर मेरी जो निजी, मौलिक और पूरी तरह आत्मकेंद्रित शोध है, वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय जर्नल में छपने लायक है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि ठंड में रोज नहाना केवल शरीर पर नहीं, आत्मा, मन, पाचन तंत्र, सरकारी कुर्सी और घर के पानी के टैंक—सब पर एक साथ अत्याचार है। फिर भी न जाने क्यों मेरा परिवार मुझे एक महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक घोषित अपराधी की तरह देखता है, जिसे हर सुबह पकड़कर गुसलखाने में ठूंसना उनका नैतिक कर्तव्य है।

मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सर्दियों में रोज नहाने से शहर में पानी का संकट पैदा होने की पूरी-पूरी संभावना रहती है। पानी वैसे ही इतना ठंडा होता है कि लगता है सीधे हिमालय से उतरकर हमारे बाथरूम में घुस आया है। अब ऐसे पानी को शरीर पर डालकर अगर कोई "फ्रेशनेस" महसूस करता है, तो या तो वह महान योगी है या फिर उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं इन दोनों श्रेणियों में नहीं आता। मेरा शरीर संवेदनशील है, आत्मा कोमल है और मेरी चमड़ी तो इतनी समझदार है कि ठंड का नाम सुनते ही सिकुड़ने लगती है।

फिर भी मेरे घरवाले हैं कि मेरे इस गहन, वैज्ञानिक और लोकहित से प्रेरित चिंतन को मसखरों का चिंतन मानते हैं। हर सुबह मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं देश का पानी बचाकर कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूं। मां का तर्क अलग, पत्नी का अलग, और बच्चों की तो अपनी ही अदालत चलती है। सब मिलकर मुझे नहलाने के लिए ऐसे एकजुट होते हैं जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश रच ली गई हो। मुझे समझ नहीं आता कि जो आदमी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए रोज ऑफिस जाता है, उसे ठंडे पानी से प्रताड़ित करना आखिर किस संविधान में लिखा है। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे जैसे त्यागी, तपस्वी, कर्तव्यनिष्ठ, कुशल, योग्य और ईमानदार कर्मचारी के जीवन में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है, तो वह धर्म है। धर्म मेरे जैसे सीधे-सादे जीव को हर कदम पर रोकता-टोकता है। रिश्वत लेने के रास्ते में धर्म सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। मैं जीवन में हर तरह के धार्मिक कष्ट सह सकता हूं, व्रत-उपवास भी झेल सकता हूं, पर रिश्वत लेने में जो मानसिक अड़चन धर्म पैदा करता है, उसे मैं किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकता। अब ऐसे में अगर नहाने जैसी अतिरिक्त धार्मिक क्रिया को रोज की दिनचर्या में जोड़ दिया जाए, तो सोचिए मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। मित्रो! मेरे फैमिली डॉक्टर का खुले चैलेंज के साथ कहना है कि सर्दियों में रोज नहाने से चाहे दुनिया पर कोई असर पड़े या न पड़े, पर पाचन तंत्र पर सीधा हमला होता है। उनका कहना है कि रोज नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। और मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में अगर मुझे किसी से सच्चा प्रेम है, तो वह मेरा पाचन तंत्र है। पाचन तंत्र ठीक तो सब ठीक। पाचन तंत्र खराब तो जीवन ही बेकार। मुझसे पहले के कई रिटायर्ड महानुभाव यह ज्ञान देकर गए हैं कि सरकारी पद पर बैठे आदमी का शरीर चाहे जैसा हो, पर पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए, ताकि उसे कुछ भी खाकर बदहजमी न हो। क्योंकि सरकारी नौकरी में खाने का समय निश्चित नहीं होता, पर खाने की विविधता अपार होती है। अब मित्रो! सर्दियों में रोज वही नहाएं जिन्हें खेतों में हल चलाना है, निर्माण स्थल पर ईंट ढोनी है, या धूल-मिट्टी में दिन भर लोटना है। मुझे तो केवल ऑफिस जाकर कुर्सी तोड़नी है। सुबह बारह बजे गिरते-पड़ते ऑफिस पहुंचना है, दो-चार बार चाय-शाय पीनी है, कुर्सी पर कभी इस करवट बैठना है तो कभी उस करवट। जब कुर्सी पर दाएं-बाएं पलटते-पलटते कमर जवाब दे दे, तो आसपास के कमरों में ताजा खबरें सुनने निकल जाना है। कोई फरियादी अगर गलती से काम करवाने आ गया, तो उसे लताड़कर ऐसा अनुभव देना है कि वह दोबारा आने से पहले सात जन्म सोचता रहे। देखते-देखते लंच हो जाता है। घर से लाया लजीज टिफिन रगड़ा जाता है और फिर धूप सेंकने के लिए कमरे से बाहर निकलना होता है।

बंधुओ! मेरी कुर्सी की डायरेक्शन भी बड़ी रहस्यमयी है। सर्दियों में मेरी कुर्सी के पास धूप शाम पांच बजे के बाद आती है, जब ऑफिस खत्म होने वाला होता है। अब बताइए, ऐसे में हीटर कितनी देर चलाया जाए? हीटर चलाओ तो बिजली बिल का डर, न चलाओ तो हड्डियों में आवाज आने लगती है। ऊपर से मोटी चमड़ी में खुश्की के साथ खुजली अलग शुरू हो जाती है। और मजे की बात देखिए—गर्मियों में, जब धूप की कोई जरूरत नहीं होती, तब मेरे ऑफिस में आने से पहले ही मेरी कुर्सी हीटर की तरह तप चुकी होती है। बैठते ही ऐसा लगता है जैसे किसी तंदूर पर बैठ गए हों।

ट्रंप के 500% टैरिफ हथौड़े का वार बेअसर करेगी मोदी की ढाल, देखती रह जायेगी दुनिया

> हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की इस आक्रामक नीति से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ने की आशंका है। यूरोपीय संघ के लिए यह चेतावनी है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी को भी निशाना बना सकता है।

अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर वैश्विक व्यापार में नया तूफान खड़ा कर दिया है। इस कदम को सीधे तौर पर भारत, चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों के खिलाफ दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका पहले से ही भारत पर ऊंचे टैरिफ लागू कर चुका है लेकिन इसके बावजूद भारत का निर्यात तेजी से बढ़ा है और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। देखा जाये तो अमेरिकी राजनीति में आक्रामक व्यापार नीति की वापसी हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर की टैरिफ भाषा जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है जिससे यह संकेत भी मिला है कि वह जलवायु और व्यापार दोनों मोर्चों पर बहुपक्षीय सहयोग से पीछे हट रहा है। अमेरिका की इस रणनीति से सिर्फ भारत या चीन ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ भी असहज है और वहां भी अमेरिकी धमकियों को लेकर बेचैनी बढ़ रही है।

वैसे भारत की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में अलग दिखाई देती है। हालिया आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात तीन वर्षों की सबसे तेज दर से बढ़ा है। घरेलू मांग में मजबूती, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं, विनिर्माण को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने से भारतीय उद्योग को नया आत्मविश्वास मिला है। साथ ही मोदी सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देकर और सुधारों को तेज कर यह संदेश दिया है कि बाहरी दबावों के आगे झुकने की बजाय भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा।

हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की इस आक्रामक नीति से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ने की आशंका है। यूरोपीय संघ के लिए यह चेतावनी है कि अमेरिका अपने हितों के लिए किसी को भी निशाना बना सकता है। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह दबाव की कूटनीति से नहीं बल्कि आर्थिक ताकत से जवाब देगा।

देखा जाये तो अमेरिका का 500 प्रतिशत टैरिफ का शोर दरअसल डर की राजनीति है। यह उस व्यवस्था की घबराहट को दिखाता है जो दुनिया के बदलते आर्थिक संतुलन को स्वीकार नहीं कर पा रही। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वह न तो किसी के सामने झुकने को तैयार है और न ही टकराव की बेकार लड़ाई में पड़ना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति साफ है यानि सीधी भिड़ंत नहीं बल्कि नीतिगत प्रहार किया जाये।

देखा जाये तो मोदी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जो सुधार किए हैं वे आज इस संकट के समय ढाल बनकर सामने आ रहे हैं। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं हों या विदेशी निवेश के लिए नियमों का सरलीकरण हो, हर कदम का मकसद एक ही है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। घरेलू उपभोक्ता बाजार की ताकत को सरकार ने रणनीतिक हथियार में बदला है। जब बाहरी बाजार दबाव बनाते हैं तब भीतर की मांग अर्थव्यवस्था को संभाल लेती है।

यदि अमेरिका सचमुच भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाता है तो मोदी के पास कई विकल्प हैं। पहला है निर्यात बाजारों का और विविधीकरण। हम आपको बता दें कि भारत पहले ही एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दूसरा उपाय है घरेलू विनिर्माण को और आक्रामक समर्थन। तीसरा उपाय है व्यापार समझौतों को तेज करना ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। चौथा उपाय है विश्व व्यापार संगठन जैसे मंचों पर कानूनी और कूटनीतिक लड़ाई।

वैसे अमेरिका की यह नीति खुद उसके लिए भी जोखिम भरी है। यूरोपीय संघ और चीन के साथ एक साथ टकराव वैश्विक मंदी को न्योता दे सकता है। भारत इस पूरे खेल में संतुलन की भूमिका निभा रहा है। न तो आंख दिखा रहा है और न ही आंख झुका रहा है। यही रणनीतिक परिपक्वता है। देखा जाये तो डोनाल्ड ट्रंप की शैली टैरिफ धमकी और दबाव पर आधारित रही है लेकिन मोदी की शैली नीतियों और सुधारों पर टिकी है। दोनों नेताओं के बीच यही मूल फर्क है। भारत ने दिखा दिया है कि टैरिफ से डर कर फैसले नहीं बदले जाते बल्कि अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाता है कि टैरिफ बेअसर हो जाएं।

उधर, अमेरिका के सौर गठबंधन से हटने का फैसला भी यही बताता है कि वह सहयोग की नहीं बल्कि नियंत्रण की राजनीति चाहता है। इसके उलट भारत बहुपक्षीय सहयोग का पक्षधर रहा है। यही कारण है कि आज भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज माना जा रहा है। देखा जाये तो आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि आत्मविश्वास की कहानी है। निर्यात का बढ़ना, घरेलू मांग का मजबूत होना और सुधारों की निरंतरता यह सब बताता है कि भारत सही दिशा में है। अमेरिका चाहे जितनी भी ऊंची दीवार खड़ी करे भारतीय अर्थव्यवस्था उसके ऊपर से रास्ता निकाल लेगी। साथ ही यूरोपीय संघ और चीन के लिए भी यह समय आत्ममंथन का है। अमेरिकी दबाव के आगे झुकना समाधान नहीं है। भारत ने यह रास्ता दिखा दिया है कि आर्थिक मजबूती ही सबसे बड़ा जवाब है। इसलिए यह साफ है कि टैरिफ की राजनीति अल्पकालिक हथियार है जबकि सुधार और आत्मनिर्भरता दीर्घकालिक शक्ति हैं। मोदी की नीतियां इसी दीर्घकालिक सोच पर आधारित हैं। अगर अमेरिका 500 प्रतिशत टैरिफ का हथौड़ा उठाता है तो भारत के पास नीति सुधार, उपभोक्ता शक्ति और वैश्विक साझेदारी की पूरी ढाल मौजूद है। यही वजह है कि शोर चाहे जितना भी तेज हो, भारत की चाल शांत लेकिन घातक बनी हुई है।

बहरहाल, अमेरिका चाहे यह कह दे कि व्यापार समझौता इसलिए अटका क्योंकि मोदी ने फोन नहीं किया, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। मोदी ऐसे नेता नहीं हैं जो दबाव में आकर या किसी के इशारे पर फैसले लें। भारत की नीति फोन कॉल से नहीं, राष्ट्रीय हित से तय होती है। अगर शर्तें देश के हित में नहीं हैं, तो मोदी पीछे हटने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि भारत आज आत्मविश्वास के साथ दुनिया से बात करता है। अमेरिका को यह समझना होगा कि नया भारत सम्मान चाहता है, आदेश नहीं। मोदी की विदेश नीति साफ है, बराबरी पर बात होगी, दबाव में नहीं।

प्रेरणा

जिसके पास कुछ नहीं था, उसी के पास सब कुछ था

इतिहास में बहुत कम ऐसे क्षण होते हैं जब किसी सम्राट का जीवन तलवार या युद्ध से नहीं, बल्कि एक साधारण व्यक्ति की शांति से बदल जाता है। सम्राट अशोक के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आया, जिसने उनकी सोच, उनके शासन और उनके अस्तित्व की दिशा ही बदल दी। वह कोई भव्य सभा नहीं थी, न कोई धार्मिक अनुष्ठान, न किसी विद्वान का लंबा उपदेश। वह तो बस एक शांत मार्ग था, एक साधारण बौद्ध भिक्षु और उसके हाथ में रखा एक मिट्टी का कटोरा।

अशोक उस दिन अपने साम्राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। उनके साथ सेना थी, अधिकारी थे, दास-दासियां थीं। हर ओर राजसत्ता का वैभव फैला था। लोग उन्हें देखकर भय और सम्मान से झुक जाते थे। पर उसी यात्रा में उनकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी, जो न झुका, न डरा, न प्रभावित हुआ। वह भिक्षु शांत भाव से बैठा था, जैसे संसार की सारी हलचल उससे दूर हो। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी।

अशोक ने सहज जिज्ञासा से पूछा, "तुम्हारे पास बस यही है?" भिक्षु ने अपने मिट्टी के कटोरे की ओर देखा और मुस्कराकर कहा, "महाराज, इससे अधिक की मुझे आवश्यकता नहीं।" यह उत्तर साधारण शब्दों में था, पर उसमें एक गहरा सत्य छिपा था। वह सत्य अशोक के भीतर गूंज उठा। उनके पास सब कुछ था—राज्य, शक्ति, सम्मान, धन—फिर भी मन अशांत था। और सामने खड़ा व्यक्ति, जिसके पास कुछ भी नहीं था, पूर्ण संतोष में था। यहीं से अशोक के भीतर एक मौन संवाद शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को देखा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जिन विजयों पर गर्व किया, वे सब दूसरों पर थीं, स्वयं पर नहीं। उन्होंने देखा कि सत्ता भय पैदा कर सकती है, पर शांति नहीं। धन सुविधाएं दे सकता है, पर संतोष नहीं। सेना सुरक्षा दे सकती है, पर निश्चिंतता नहीं। उस भिक्षु की आंखों में जो शांति थी, वह किसी भी राजमहल में नहीं मिल सकती थी।

अशोक को यह बोध हुआ कि असली निर्धनता वस्तुओं की कमी नहीं, बल्कि इच्छाओं की अधिकता है। और असली समृद्धि वस्तुओं का ढेर नहीं, बल्कि मन की तृप्ति है। उस मिट्टी के कटोरे ने उन्हें यह सिखा दिया कि आवश्यकता सीमित हो तो जीवन सरल हो जाता है। पर जब इच्छाएं असीम हो जाती हैं, तब पूरा संसार भी छोटा पड़ जाता है।

यह अनुभव अशोक के भीतर धीरे-धीरे गहराता गया। उन्होंने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उन्हें अपने क्रोध, अपने अहंकार, अपनी हिंसा का बोध हुआ। कलिंग युद्ध की स्मृतियां उनके सामने जीवित हो उठीं। हजारों निर्दोषों का रक्त, विधवाओं का विलाप, बच्चों की चीखें—सब उनके अंतर्मन में उतर आईं। पहली बार उन्हें लगा कि उन्होंने जो जीता, वह वास्तव में हार थी। और जो उस भिक्षु ने छोड़ा, वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।

इसके बाद अशोक के लिए शासन का अर्थ बदल गया। उन्होंने समझा कि राजा का काम केवल आदेश देना नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व निभाना है। प्रजा को डराकर चलाया जा सकता है, पर सम्मान देकर जोड़ा जा सकता है। उन्होंने दंड की जगह सुधार को चुना। उन्होंने हिंसा की जगह करुणा को अपनाया। धर्म उनके लिए अब सत्ता का उपकरण नहीं रहा, बल्कि आत्मा की आवाज बन गया।

अशोक ने जाना कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही वास्तव में सम्राट होता है। बाहरी सिंहासन अस्थायी होता है, पर आंतरिक सिंहासन स्थायी। जिसने अपने मन पर शासन कर लिया, उसे किसी और पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि अशोक का नाम केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि मानवता की स्मृति में जीवित है।

वह भिक्षु, जिसका नाम इतिहास ने दर्ज नहीं किया, वास्तव में सबसे बड़ा शिक्षक था। उसने न तो उपदेश दिया, न कोई दावा किया, फिर भी उसने एक सम्राट की आत्मा को जगा दिया। उसकी संपत्ति शून्य थी, पर उसका प्रभाव असीम। यही सच्ची शक्ति होती है—जो दिखती नहीं, पर बदल देती है।

आज के समय में यह कथा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आज मनुष्य के पास सुविधाएं पहले से कहीं अधिक हैं, पर शांति पहले से कहीं कम। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, संतोष घटता जा रहा है। हम सब किसी न किसी रूप में अशोक हैं—बाहरी सफलताओं से घिरे, पर भीतर बेचैन। और हम सबको उस भिक्षु की तरह किसी क्षण की आवश्यकता है, जो हमें याद दिला दे कि जीवन का मूल्य संग्रह में नहीं, संतुलन में है।

जिसके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है, वह भीतर से रिक्त है। और जिसके पास कम है, पर मन शांत है, वही वास्तव में समृद्ध है। यही उस कथा का सार है। यही वास्तविक सम्राट की पहचान है। जिसने संसार को नहीं, स्वयं को जीत लिया—वही सच्चा विजेता है।

तमिल जन आकांक्षाओं के विजयी सेनापति

कुछ लोग उन्हें दक्षिण का एंग्री यंगमैन बता रहे हैं, तो कुछ राजनीति के जरिये सामाजिक-सांस्कृतिक उद्धार करने वाला सेनापति। दक्षिण भारत में फिल्मों से राजनीति में वर्चस्व करने वालों की कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है सुपर स्टार विजय का। राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने फिलहाल फिल्मों से किनारा कर लिया है। हिट थलपति-69 को उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है। इसी वजह से अब उन्हें थलपति विजय का नाम दिया जा रहा है। दरअसल, थलपति का तमिल में मतलब सेनापति होता है। उन्होंने बाकायदा पार्टी का झंडा व चिन्ह भी लॉन्च किया है और अब उनकी पार्टी टीवीके को चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है। कहा जा रहा है कि इस साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी बड़ा राजनीतिक उलट फेर कर सकती है। उनकी सभाओं में जुटने वाली लाखों की भीड़ कम से कम यही इशारा कर रही है।

बहरहाल, आज विजय महज फिल्म स्टार भर नहीं हैं, उन्हें तमिलनाडु के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव के वाहक के रूप में देखा जा रहा है। उनके चाहने वालों में सिर्फ फिल्म प्रेमी ही नहीं हैं, बल्कि वे युवा भी हैं जो बेहतर रोजगार की स्थिति, साफ-सुथरी राजनीति और तमिल अस्मिता की रक्षा की आकांक्षा रखते हैं। वे सभाओं में कहते हैं कि हम बांटने वाली राजनीति के खिलाफ हैं। वे द्रविड़ राजनीति के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की निंदा करते हैं। वे एक परिवार पर राज्य को लूटने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि हम द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं करेंगे। पार्टी की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि पार्टी की सोच धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय विचारधारा पर टिकी होगी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी संत पेरियर के बताये रास्ते पर चलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्त्री सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय रहा है। यद्यपि उन्होंने पेरियर के नास्तिकता से जुड़े सिद्धांत से असहमति जतायी है।

दरअसल, विजय के इस अभियान से जुड़ने वाले सिर्फ उनके फिल्मों के प्रशंसक ही नहीं हैं। दरअसल, युवा उन्हें बदलाव के वाहक नायक के रूप में देख रहे हैं। युवा उन्हें अपनी आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि विजय उनके मन की बात कर रहे हैं। दरअसल, विजय की फिल्मों का नायक एक ऐसा यंग एंग्रीमैन होता है जो सिस्टम की विसंगतियों के खिलाफ विद्रोह करता है। जैसा कभी हिंदी फिल्मों में सत्तर के दशक में अमिताभ बच्चन करते दिखाई देते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि सिनेमाघर में बोला गया उनका हर संवाद सड़कों पर नारे की शक्ल में आता रहा है। यही वजह है कि आज उन्हें थलपति विजय के नाम से संबोधित किया जा रहा है, जो युवा मनोविज्ञान का प्रतिनिधि चेहरा बन गया है। दरअसल, अन्य राज्यों की तरह ही तमिलनाडु का युवा समकालीन विसंगतियों से जूझ रहा है। इसमें- बेरोजगारी का संत्रास है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की हताशा है, गैर-बराबरी बढ़ाने वाला विकास है तो तमिलनाडु के राजनेताओं से मोहभंग की स्थिति भी है। यही वजह है कि विजय की घोषणाएं युवाओं को लुभाती हैं और उन्हें विश्वास है कि विजय फिल्मों में निभाए किरदार जैसी भूमिका से समाज में बदलाव ला सकते हैं। वैसे भी तमिलनाडु में फिल्मी सितारों के प्रति जुनून का पुराना इतिहास रहा है। मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में वे हर प्लेट फॉर्म में छाए हुए हैं। अब चाहे रील्स हों, मीम्स हों या वायरल संवाद, वे हर जगह नजर आते हैं। आज की एक हकीकत यह भी है कि यह ऑनलाइन लोकप्रियता अब हकीकत में भी नजर आने लगी है।

दरअसल, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये थलपति विजय कमर कसकर आए हैं। निश्चित रूप से 2026 में तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव खासा रोचक होने जा रहा है। माना जा रहा है कि वे राज्य में डीएमके व एआईडीएमके के वर्चस्व को कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। वे एक सधे राजनेता की तरह बात करते हैं। वे राज्य में दो भाषाओं के समर्थक हैं- यानी सरकारी कामकाज में तमिल व अंग्रेजी का उपयोग। वे जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। साथ ही भविष्य में किसी राजनीतिक गठबंधन से भी इनकार नहीं करते हैं। बहरहाल, विजय आज तमिलनाडु की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक बदलाव के लिये उन्होंने फिल्में छोड़ दी हैं। राजनीति में आने पर वे सिर्फ समाजसेवा करेंगे।

बहरहाल, अब दक्षिण भारत में एमजी रामचंद्रन, जयललिता, विजयकांत, एनटी रामाराव व कमल हासन व पवन कल्याण जैसे सुपरस्टारों की राजनीतिक कामयाबी में थलपति विजय का नाम भी जुड़ने जा रहा है। पवन कल्याण आंध्र की राजनीति में कमाल करके उप-मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उन्होंने जन सेना नामक राजनीतिक दल बनाया। वे एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। वे राजनीतिक दल बनाने वाले प्रसिद्ध एक्टर चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। चिरंजीवी ने भी प्रजा राज्यम पार्टी बनायी थी। कालांतर वे राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय मंत्री भी बने।

जहां तक तमिलनाडु में फिल्म सितारों के राजनीतिक वर्चस्व का सवाल है तो मशहूर अभिनेता एम.जी. रामचंद्रन ने एआईएडीएमके बनाई और एक दशक तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। फिर चर्चित अभिनेत्री जयललिता भी इसी पार्टी में शामिल होकर पहली बार 1991 में मुख्यमंत्री बनीं। वहीं दूसरी ओर अभिनेता कमल हासन भी वर्ष 2018 में मक्कल 'नीधि मय्यम पार्टी' बना चुके हैं। लगता है कि इस कड़ी में नया नाम थलपति विजय का जुड़ने जा रहा है।

अभियान

राम मंदिर के 15 किलोमीटर दायरे में मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध, ऑनलाइन डिलीवरी भी रडार पर

रामनगरी अयोध्या में आस्था, परंपरा और धार्मिक भावनाओं को केंद्र में रखते हुए प्रशासन ने एक अहम और सख्त फैसला लिया है। राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की आपूर्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध केवल स्थानीय दुकानों और होटलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन खाद्य सेवाओं के जरिए की जाने वाली मांसाहारी भोजन की डिलीवरी पर भी लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि पंच कोसी परिक्रमा क्षेत्र में बार-बार मिल रही शिकायतों और धार्मिक मर्यादाओं के उल्लंघन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

दरअसल, बीते कुछ समय से अयोध्या प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि प्रतिबंध के बावजूद ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मांसाहारी भोजन मंगाया जा रहा है। खासकर पंच कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने इस पर आपत्ति जताई थी। लोगों का कहना था कि राम मंदिर और उससे जुड़े पवित्र क्षेत्रों की गरिमा के विपरीत इस तरह की गतिविधियां न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान पर भी प्रश्नचिह्न लगाती हैं।

इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने शुक्रवार को स्पष्ट आदेश जारी किया कि राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की किसी भी प्रकार की आपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी। सहायक खाद्य आयुक्त माणिक चंद्र सिंह ने बताया कि पहले भी मांस और शराब की बिक्री को लेकर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन कुछ लोग तकनीकी रास्तों से नियमों को दरकिनार कर रहे थे। ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मांसाहारी भोजन की आपूर्ति उसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अब इस पर पूर्ण विराम लगाने का निर्णय लिया गया है।

प्रशासन के अनुसार, इस प्रतिबंध की सूचना सभी होटलों, गेस्ट हाउस, होमस्टे, दुकानदारों और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को दे दी गई है। साफ निर्देश हैं कि यदि कोई प्रतिष्ठान या डिलीवरी एजेंसी इस आदेश का उल्लंघन करती पाई गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल आदेश जारी कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन पर यह दबाव भी है कि वह अयोध्या को एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उसी स्वरूप में बनाए रखे, जैसा उसकी ऐतिहासिक पहचान रही है। अधिकारियों का मानना है कि मांसाहार और मादक पदार्थों की खुलेआम उपलब्धता इस छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले अयोध्या नगर निगम ने पिछले वर्ष मई में एक अहम निर्णय लिया था। इसके तहत अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे राम पथ पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस समय यह फैसला भी धार्मिक भावनाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया था। हालांकि, नौ महीने बीत जाने के बाद भी इस निर्णय का व्यापक असर पूरी तरह देखने को नहीं मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि राम पथ पर आज भी दो दर्जन से अधिक दुकानें खुलेआम शराब बेच रही हैं। इस देरी और ढिलाई को लेकर प्रशासन पर सवाल भी उठे हैं। जब इस संबंध में एक नगर निगम अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि निगम ने फैजाबाद और राम पथ क्षेत्र में स्थित मांस की दुकानों को हटाने की कार्रवाई की थी। लेकिन शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करना केवल नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति आवश्यक होती है। यही वजह है कि शराब बिक्री पर प्रतिबंध को पूरी तरह लागू करने में समय लगा है।

फिर भी, प्रशासन का दावा है कि अब वह किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। ऑनलाइन मांसाहारी भोजन आपूर्ति पर प्रतिबंध को इसी सख्ती की कड़ी माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पहले लोग यह तर्क देते थे कि दुकानें बंद हैं, लेकिन निजी तौर पर या ऑनलाइन माध्यम से मांसाहारी भोजन मंगाया जा सकता है। अब इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, ताकि नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित हो सके।

होटल और होमस्टे को लेकर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में ऐसी शिकायतें सामने आई थीं कि कुछ होटल और होमस्टे अपने मेहमानों को मांसाहारी भोजन और मादक पेय परोस रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने संबंधित प्रतिष्ठानों को कड़ी चेतावनी दी है। साफ कहा गया है कि अयोध्या जैसे धार्मिक नगर में इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि कोई होटल या होमस्टे नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अयोध्या केवल एक शहर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहां के नियम और व्यवस्थाएं उसी अनुरूप होनी चाहिए। उनका मानना है कि मांसाहार और शराब पर प्रतिबंध से न केवल धार्मिक भावनाओं की रक्षा होगी, बल्कि अयोध्या की पहचान एक पवित्र तीर्थ नगरी के रूप में और मजबूत होगी।

हालांकि, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना ज्यादा जरूरी है। पिछले अनुभवों को देखते हुए लोगों को आशंका है कि कहीं यह फैसला भी कागजों तक ही सीमित न रह जाए। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बिना भेदभाव के कार्रवाई करे।

कुल मिलाकर, राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध अयोध्या प्रशासन की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें धार्मिक मर्यादाओं और आस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह निर्णय किस हद तक प्रभावी रूप से लागू हो पाता है और क्या अयोध्या वास्तव में मांस और शराब से मुक्त धार्मिक नगरी के रूप में अपनी पहचान को और सुदृढ़ कर पाती है या नहीं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर का उद्घाटन किया

▶▶ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह चिंतन शिविर नए भारत के निर्माण में माइनिंग सेक्टर का रोडमैप तैयार करने का सक्षम मंच बनेगा : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▶▶ भारत का खनन क्षेत्र 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी

▶▶ खनिज संपदा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल

▶▶ बिहार के उप मुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के खान मंत्री हुए सहभागी

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा गुरुवार को महात्मा मंदिर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज चिंतन शिविर में कहा कि यह चिंतन शिविर नए भारत के निर्माण का रोडमैप तैयार करने का एक सक्षम मंच बनेगा।

केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में प्रथम तीन दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें देश के विभिन्न राज्यों के खान मंत्री और पदाधिकारियों सहित हितधारक भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों सर्वश्री जी. किशन रेड्डी, सी.आर. पाटिल, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय खान राज्य मंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस तीन दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खान-खनिज देश के उद्योगों एवं अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह चिंतन शिविर सामूहिक चिंतन-मंथन के माध्यम से इस आधार स्तंभ को और मजबूत बनाकर देश के विकास को एक नई गति देने का प्लेटफार्म प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर में होलिस्टिक एप्रोच के साथ रिफॉर्म्स (सुधार) लाए हैं। खनन क्षेत्र भी ऐसे रिफॉर्म्स का साक्षी रहा है। स्पष्ट नीतियों, राजनीतिक इच्छा शक्ति और पारदर्शी शासन के परिणामस्वरूप ये रिफॉर्म्स संभव हो पाए हैं।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करने की जो परंपरा स्थापित की है, और ग्रीन माइनिंग, साइंटिफिक रेक्लेमेशन और

टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी से खनन क्षेत्र का विकास किया है।

मुख्यमंत्री ने गुजरात को लिग्नाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट जैसे मुख्य खनिजों के लिए एक अहम स्थान बताते हुए कहा कि खान-खनिज क्षेत्र को केवल उत्पादकता और नीलामी तक सीमित न रखते हुए गुजरात ने इसे पारदर्शिता, अनुशासन और नियम-कानूनों के अमल का प्रतीक भी बनाया है।

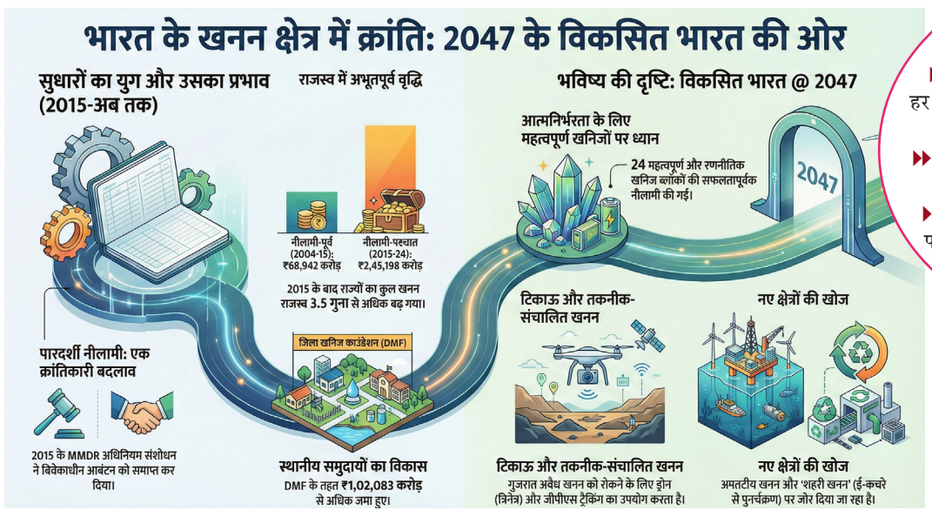

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खान से लेकर अंतिम गंतव्य स्थल तक के खनिज परिवहन की रीयल टाइम निगरानी के लिए जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि गुजरात अपनी खनिज संपदाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' से 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को साकार करने को प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र को भारत के आर्थिक विकास और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मजबूत आधार स्तंभ करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुजरात आज पूरे देश के लिए विकास का केंद्र बन गया है। गुजरात के मॉडल का अनुसरण करके आज देश के अनेक राज्यों के बीच विकास और निवेश के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने पिछले 11 वर्षों में खनन क्षेत्र में आए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2014 की तुलना में मिनरल एक्सप्लोरेशन यानी खनिज अन्वेषण में 190 फीसदी की वृद्धि हुई है। आयरन, लाइमस्टोन, लेड और जिंक जैसे खनिजों के उत्पादन में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। पारदर्शी नीलामी प्रणाली और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमडब्ल्यू) के माध्यम से राज्यों के खनन राजस्व में बड़ा उछाल आया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने लिथियम, कोबाल्ट और टंगस्टन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष जोर दिया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▶▶ प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर सेक्टर में होलिस्टिक एप्रोच के साथ रिफॉर्म्स लाए हैं

▶▶ गुजरात लिग्नाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट जैसे मुख्य खनिजों के लिए एक अहम क्षेत्र

▶▶ गुजरात अपनी खनिज संपदाओं के द्वारा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत से 'विकसित भारत@2047' का संकल्प साकार करने में योगदान देने को प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा कि भारत अब केवल खनिजों के निष्कर्षण (पृथ्वी से खनिज निकालने की प्रक्रिया) तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिफाइनिंग, रीसाइक्लिंग और रीप्रोसेसिंग की पूरी 'वैल्यू चेन' पर ध्यान दे रहा है। वर्ष 2030 तक ई-वेस्ट से क्रिटिकल मिनरल्स को रिकवर करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की गई हैं।

उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य अगले पांच वर्षों के लिए रणनीतिक योजना तैयार करना है। इसमें खनिज ब्लॉकों की नीलामी से लेकर ऑपरेशन तक के समय को न्यूनतम करना, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण का उपयोग बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके भारत को ग्लोबल प्रोसेसिंग हब बनाना जैसे विषयों पर अधिकतम फोकस करना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनर्उपयोग के लिए 'अर्बन माइनिंग' और 'वेस्ट टू वेल्थ' के विचार को गति देने का आह्वान किया।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में खनिज क्षेत्र और जल प्रबंधन का परस्पर समन्वय बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जब 'विकसित भारत' बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, ऐसे में खनिज संपदा को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहना गलत नहीं होगा। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति में इस मंत्रालय की भूमिका निर्णायक है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि खनिज उत्खनन के दौरान पर्यावरण और जल संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने 'माइनिंग विद माइंडफुलनेस' का मंत्र देते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन के साथ खनन कार्य करने से ही दीर्घकालिक लाभ होगा। खनन प्रक्रिया में पानी का रीसाइकल और रीयूज अनिवार्य है। उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से उपयोग करने की बात कही जिससे भूमिगत जलस्तर को नुकसान न पहुंचे।

श्री पाटिल ने कहा कि भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर हम आयात पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाएगी और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करेगी। शिविर के दौरान उन्होंने खान विभाग द्वारा अपनाई गई पारदर्शिता और कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाली डिजिटल और नवीन पद्धतियों की प्रशंसा की।

केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने चिंतन शिविर को भारत के खनन क्षेत्र के भविष्य के लिए एक निर्णायक मार्ग बताते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संग्रह के लिए आवश्यक बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 'क्रिटिकल मिनरल्स' के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ऐसी खानों की नीलामी और उत्पादन प्रक्रिया को तेज बना रही है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक उपकरणों का खनन क्षेत्र में उपयोग अनिवार्य है, जिससे न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि प्रदूषण, लागत और समय में भी उल्लेखनीय बचत होगी।

खनिज विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए श्री दुबे ने कहा कि खनन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करना और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ किया कि इस क्षेत्र में केवल सरकार की भागीदारी ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के साथ कदम मिलाकर चलना होगा।

चिंतन शिविर के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय खनन सचिव श्री पीयूष गोयल ने स्वागत भाषण दिया।

कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के मंत्री श्री कोल्लू रवीन्द्र, ओडिशा के मंत्री श्री विभूति भूषण जेना, तेलंगाना के मंत्री श्री विवेक वेंकट स्वामी, उत्तर प्रदेश के मंत्री डॉ. अरुण कुमार, नागालैंड के मंत्री श्री चीनवेंग, गुजरात की उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा सहित केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारी मौजूद रहे।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है, जो 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपर्युक्त कार्य के संबंध में कांदिवली स्थित कार शेड लाइन पर प्वाइंट नंबर 104 को हटाने हेतु 11/12 जनवरी, 2026 की रात्रि में एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 23:15 बजे से 03:15 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त, 12/13 जनवरी, 2026 को कांदिवली में क्रॉसओवर 101/102/103/104 को जोड़ने के लिए एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक अप फास्ट लाइन पर 23:15 बजे से 03:15 बजे तक और डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक कांदिवली और मालाड के बीच लागू रहेगा। उपर्युक्त ब्लॉकों, पांचवीं लाइन के निलंबन तथा गति प्रतिबंध लगाए जाने के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी।

ब्लॉक के कारण प्रभावित होने वाली उपनगरीय ट्रेनों की विस्तृत सूची अनुलग्नक–I एवं II में दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की रवाडी (पालखी यात्रा) में ढोल-ताशों ने जमाया भारी आकर्षण

ढोल-ताशों के 50 कलाकारों द्वारा उमंगोल्लासपूर्ण वादन के साथ यात्री भी नाच उठे, तीन ढोल टूटे

(जीएनएस)। गांधीनगर : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत शुक्रवार को भव्य रवाडी (पालखी यात्रा) के दौरान समग्र सोमनाथ नगरी भक्ति एवं उत्साह से गूंज उठी। रवाडी में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्त तथा श्रद्धालु बड़ी संख्या में सहभागी हुए।

इस रवाडी के दौरान ढोल-ताशा कलाकारों ने अपनी मनमोहक तथा उमंगोल्लासपूर्ण प्रस्तुति से विशेष आकर्षण उत्पन्न किया। लगभग 50

कुशल कलाकारों ने ढोल और ताशों के ताल-लय के साथ परंपरागत संगीत की प्रस्तुति कर वातावरण को रंगीन बना दिया। गगनभेदी नाद के साथ यात्री भी नाच उठे। वादन इतना उत्साहपूर्ण था कि लगभग तीन ढोल टूट गए। ढोल-ताशों के गूंजते नाद के साथ रवाडी आगे बढ़ रही थी, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर खड़े दर्शकों में भी उत्साह दिखाई दे रहा था। कलाकारों की एकीकृत प्रस्तुति ने समग्र कार्यक्रम को लोकोत्सव के स्वरूप में रूपांतरित कर दिया।

रवाडी के दौरान भक्तों द्वारा जय शिवशंकर तथा हर हर महादेव के उद्घोष के साथ सनातन संस्कृति की महिमा गुंजाई गई। ढोल-ताशों के ताल के साथ भक्ति तथा आनंद का अनूठे संगम का सृजन हुआ।

इस प्रकार; सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अंतर्गत निकली रवाडी में ढोल-ताशा कलाकारों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम की भव्यता तथा सांस्कृतिक वैभव को और उजागर कर सभी उपस्थितों के लिए इस क्षण को यादगार बना दिया।

VGRC राजकोट में RBSM के दौरान 1,500 से अधिक MoUs, 110 अंतरराष्ट्रीय खरीदार और 1,800 से अधिक B2B बैठकों के साथ होगा भव्य आयोजन

VGRE राजकोट में आयोजित RBSM कच्छ और सौराष्ट्र की निर्यात क्षमता को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा

(जीएनएस)। गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के तहत राजकोट में होने वाली आगामी प्रदर्शनी एक महत्वपूर्ण आयोजन बनने जा रही है, जिसमें 1,500 से अधिक समझौता ज्ञापन (MoUs) होने की उम्मीद है। इस प्रदर्शनी में 110 अंतरराष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे, और रिवर्स बायर सेलर मीट (RBSM) के दौरान 1,800 से अधिक व्यावसायिक बैठकें निर्धारित की गई हैं। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए यह प्रदर्शनी 11 से 15 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद सम्मेलन का उद्घाटन सत्र आयोजित होगा, जिससे वैश्विक व्यापार नेताओं के राजकोट में एकत्र होने की पृष्ठभूमि तैयार होगी।

26,000 वर्ग मीटर में फैली यह प्रदर्शनी 400 से अधिक प्रदर्शकों के लिए नए अवसर देगी, जो विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें एग्रो और फूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन, रक्षा, ऊर्जा, पेट्रो-केमिकल्स, इंजीनियरिंग, तथा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। साथ ही टोरेंट पावर लिमिटेड, कोसोल, अडानी ग्रीन, एस्सार ग्रुप, नायरा एनर्जी, ज्योति सीएनसी और कई अन्य प्रमुख कॉरपोरेट्स

की भी भागीदारी होगी।

रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट (RBSM) स्थानीय एमएसएमई, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्यमों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित करेगा। इस सम्मेलन के लिए 1,800 से अधिक बी2बी बैठकों की योजना बनाई गई है, जिनके दौरान 1,500 से अधिक MoUs होने की उम्मीद है। इन बैठकों में 16 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 अंतरराष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे, जिनमें अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, और ये इंजीनियरिंग, कृषि और वस्त्र जैसे विविध क्षेत्रों से होंगे। इसके अतिरिक्त, 20 राष्ट्रीय खरीदार भी इन बैठकों का हिस्सा होंगे, जिससे सहयोग और विकास के अवसर और मजबूत होंगे।

इस प्रदर्शनी को छह थीम आधारित डोम में आयोजित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक उभरते अवसरों और सतत नवाचारों को उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें गेटवे टू ग्लोबल ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम एंड पेट्रोकेमिकल्स, क्राफ्ट्स विलेज एंड एमएसएमई पैविलियन, ओशन ऑफ अपॉर्च्युनिटीज, एंटरप्राइज एक्सीलेंस पैविलियन और पब्लिक सेक्टर पावरहाउस शामिल हैं। प्रत्येक डोम में एक समर्पित डिस्प्ले पॉप-अप स्टेज भी होगा, जो प्रदर्शकों को नए उत्पाद लॉन्च करने, अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने और आगंतुकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के विशेष अवसर प्रदान करेगा।

यह आयोजन नवप्रवर्तकों, उद्यमियों, निवेशकों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, विदेशी खरीदारों, कॉरपोरेट्स, सरकारी विभागों, पीएसयू और वैश्विक साझेदारों को एक साथ एक मंच पर लाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और सतत आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके।

उद्यमियों, मेंटर्स और संस्थानों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक उद्यमी मेला भी आयोजित किया जाएगा। यह सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा तथा नवाचार, उद्यम विकास और गुजरात के सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम में भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।

यह आयोजन भारत की विकास यात्रा में गुजरात की केंद्रीय भूमिका को और अधिक सशक्त रूप से रेखांकित करेगा तथा क्षेत्रीय सशक्तिकरण, वैश्विक सहयोग और सतत विकास को नई गति प्रदान करेगा।

साथ ही, यह "विकसित गुजरात" से "विकसित भारत" के विज़न को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम सिद्ध होगा।

भारतीय संस्कृति के रक्षकों तथा आस्था के केन्द्रों की महत्ता नई पीढ़ी तक पहुँचाने का स्मरण एवं सम्मान करने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है

▶▶ श्री सोमनाथ मंदिर के साथ देश के लाखों नागरिकों की शिव भक्ति तथा आस्था अखंड रूप से जुड़े हुए हैं : मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

▶▶ विश्व के कल्याण तथा मानव जाति के मंगल के लिए ऋषिकुमारों द्वारा निरंतर 72 घण्टे ओमकार जाप किया जा रहा है

▶▶ प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा तथा ड्रोन शो का आयोजन

(जीएनएस)। गांधीनगर : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की तैयारियों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए शुक्रवार को राज्य के केबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि श्री सोमनाथ मंदिर के साथ देश के लाखों नागरिकों की शिव भक्ति तथा आस्था अखंड रूप से जुड़े हुए हैं।

श्री वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी संस्कृति एवं अध्यात्म को आधार बनाकर देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में देश व राज्य के आस्था केन्द्रों की महत्ता नई पीढ़ी तक पहुँचाई जा सकी है। सोमनाथ में तीन दिनों के लिए मनाया जा रहा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व लोगों के हृदय में बसी आस्था का प्रतिबिंब है।

उन्होंने जोड़ा कि सोमनाथ मंदिर में 72 घण्टों का अखंड ओमकार जाप का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिया है। विश्व के कल्याण तथा मानव जाति के मंगल के लिए ऋषिकुमारों द्वारा निरंतर 72 घण्टे ओमकार जाप किया जा रहा है। यह पवित्र अवसर शिव भक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति का अनूठा संगम बना है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ महादेव का जीर्णोद्धार करवा कर राष्ट्र की आस्था तथा स्वाभिमान को पुनर्स्थापित किया था। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए अनेक महान आत्माओं ने बलिदान दिए हैं। उनके स्मरण एवं सम्मान के रूप में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि 10 जनवरी शनिवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र

मोदी सोमनाथ की पवित्र भूमि पर पधारने वाले हैं। उनकी उपस्थिति में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ऐतिहासिक बनेगा। प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए 108 घोड़ों की शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है तथा भव्य ड्रोन शो द्वारा इस उत्सव को विशेष आकर्षक बनाया जाएगा।

केबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्यभर से लाखों भक्त सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सहभागी होने के लिए सोमनाथ आ रहे हैं। राज्य के साधु-संतों द्वारा शुक्रवार को सोमनाथ में भव्य रेवाडी निकाली गई। राज्य सरकार द्वारा किए गए सुव्यवस्थित आयोजन, भव्य रोशनी तथा सुसज्ज व्यवस्थाओं से सोमनाथ की दिव्यता चारों ओर फैल रही है।

उन्होंने सभी समाज के नागरिकों को सनातन धर्म के इस ऐतिहासिक पर्व में सहभागी होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहेंगे।

श्री वाघाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राजकोट में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) में भी सहभागी होने वाले हैं, जो सौराष्ट्र सहित राज्य के विकास एवं निवेश के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पूर्व अनूठा उत्साह : गिरनार तीर्थक्षेत्र सहित साधु-संत भगवान सोमनाथ के दर्शनार्थ पहुँचे

▶▶ साधु-संतों की सोमनाथ के शंख चौक से मंदिर तक की पदयात्रा में शिवजी के प्रिय वाद्य डमरू के नाद की गूंज, राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा साधु-संतों की पदयात्रा में सहभागी हुए

▶▶ साधु-संतों सहित महानुभावों ने भगवान सोमनाथ के आस्थापूर्वक दर्शन किए, पदयात्रा तथा सोमनाथ मंदिर में हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना

▶▶ साधु-संतों की पदयात्रा में परंपरागत वाद्य के साथ सिद्धिविनायक ढोल ग्रुप तथा शिवभक्तिमय संगीत से सोमनाथ में भव्य तथा दिव्य वातावरण सृजित हुआ

(जीएनएस)। गांधीनगर : सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पूर्व भव्य एवं दिव्य वातावरण का सृजन हुआ है। शुक्रवार को गिरनार तीर्थक्षेत्र सहित साधु-संत सोमनाथ के शंख चौक से पदयात्रा कर देवाधिदेव भगवान महादेव के दर्शनार्थ पहुँचे। आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने वाली इस पदयात्रा में राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा, सांसद श्री राजेशभाई चुडासमा आदि महानुभाव सहभागी हुए।

इस पदयात्रा में गिरनार तीर्थक्षेत्र के श्री इंद्रभारती बापू, श्री महेंद्रनंदगिरी बापू, श्री हरिहरानंद बापू सहित साधु-संत जुड़े। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु-संतों ने भगवान शिवजी के प्रिय वाद्य डमरू के नाद की गूज से आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रसार किया। इसके अलावा; लगभग 75

ढोलवादकों वाले सिद्धिविनायक ढोल ग्रुप ने तालबद्ध प्रस्तुति से अनूठा माहौल बनाया।

इस पदयात्रा में विधायक सर्वश्री भगवानभाई बारड, अनिरुद्धभाई दवे, पूर्व सांसद सर्वश्री दीनूभाई सोलंकी, मोहनभाई कुंडारिया, अग्रणी सर्वश्री धवलभाई दवे, पुनीतभाई शर्मा, झवेरीभाई ठकरार आदि महानुभाव सहभागी हुए और उन्होंने भगवान सोमनाथ के भावपूर्ण दर्शन कर धन्यता की अनुभूति की।

इस पदयात्रा के दौरान पुष्पवर्षा के साथ साधु-संतों तथा महानुभावों का अभिवादन किया गया।

इस पदयात्रा से समग्र सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्य एवं दिव्य वातावरण का सृजन हुआ। इसके अलावा; उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी साधु-संतों के दर्शन कर धन्यता की अनुभूति की।

बैंक और नियामक टकराव नहीं, साझेदारी का रिश्ता है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का दो टूक संदेश

(जीएनएस)। मुंबई। भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एक स्पष्ट और दूरगामी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बैंक और नियामक को एक-दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए। मुंबई में आयोजित 'कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स' के तीसरे वार्षिक वैश्विक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान गवर्नर ने साफ किया कि आरबीआई की भूमिका किसी "गलतियां पकड़ने वाले इंस्पेक्टर" की नहीं, बल्कि बैंकिंग संस्थाओं के भागीदार की है। उनका कहना था कि जब बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं केंद्रीय बैंक को सहयोगी मानकर काम करेंगी, तभी पर्यवेक्षण की प्रक्रिया वास्तव में प्रभावी और सार्थक हो सकेगी।

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में वित्तीय स्थिरता, समावेशन और विकास सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि नियामक और बैंक एक-दूसरे के साथ भरोसे और सहयोग के रिश्ते में काम करें। उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि आरबीआई केवल नियम थोपने या सजा देने वाला संस्थान है। उनके अनुसार, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य व्यवस्था को दंडित करना नहीं, बल्कि उसमें सुधार लाना और उसे भविष्य के जोखिमों के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा की जाने वाली प्रवर्तन या अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को दंडात्मक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें सुधार और दिशा-निर्देशन का माध्यम समझा जाना चाहिए। अपने संबोधन में मल्होत्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि नियामक कार्रवाई के पीछे दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला, जिन संस्थानों में कमियां या अनियमितताएं पाई जाती हैं, उन्हें यह संकेत देना कि सुधार की आवश्यकता है।

पश्चिमी रेलवे

आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (रोलिंग स्टॉक) ईएमयू कारशेड मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे, मुंबई-400034। ई-निविदा अधिसूचना क्रमांक DRM/RS/2020-21/04 दिनांक 08.01.2026 को आमंत्रित करता है। कार्य का नाम: ICF Spec.No.ICF/Elec/110 Rev.) के अनुसार EMU कैब में 415 V AC, 3-फेज टॉवर एसी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग, CS01 और CS02 के साथ। कार्य की अनुमानित लागत: ₹7,77,32,500/-। ईएमडी: ₹5,38,700/-। जमा करने की तिथि और समय: दि.: 02.02.2026 को 15:00 बजे के बाद नहीं। खुलने की निर्धारित तिथि और समय: दि.: 02.02.2026 को 15:30 बजे। इसे www.ireps.gov.in के ज़रिए देखा और सबमिट किया जा सकता है। 0990

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

माघ मेला में आस्था के साथ आरोग्य का संगम, आयुर्वेद और होम्योपैथी पर श्रद्धालुओं का बढ़ता भरोसा

(जीएनएस)। प्रयागराज। माघ मेला केवल आस्था, तप और संगम स्नान का पर्व भर नहीं रह गया है, बल्कि अब यह स्वस्थ जीवन की ओर लौटने का भी बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। देश और प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मेला क्षेत्र में आयुष पद्धति पर विशेष जोर दिया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में माघ मेला क्षेत्र में आयुर्वेद और होम्योपैथी के कुल दस चिकित्सा शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें पांच आयुर्वेदिक और पांच होम्योपैथिक अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु न केवल उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि जीवनशैली से जुड़ी स्वास्थ्य सलाह भी ले रहे हैं। माघ मेला प्रभारी डॉ. मनोज ने बताया कि आयुष मंत्रालय के निर्देश पर इन चिकित्सा केंद्रों की स्थापना इस तरह की गई है कि अधिकतम श्रद्धालुओं को आसानी से उपचार मिल सके। मेला क्षेत्र के प्रमुख और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर इन अस्पतालों को रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है। मुख्य आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल परेड ग्राउंड में फोर्ट रोड के किनारे, संगम से वापसी मार्ग पर संचालित किया जा रहा है, जहां स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्वास्थ्य परामर्श के लिए पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र की काली सड़क के समीप और अन्नपूर्णा मार्ग पर भी अस्पताल सक्रिय हैं, ताकि कल्पवासियों और दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को लंबे रास्ते तय न करने पड़ें।

यमुना नदी के तट पर अरैल क्षेत्र में विशेष रूप से दो अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जहां कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है। इन केंद्रों पर अनुभवी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। दिन-रात चलने वाले इन चिकित्सा शिविरों में श्रद्धालुओं की जांच, परामर्श और उपचार पूरी तत्परता से किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या को समय रहते नियंत्रित किया जा सके।

डॉ. मनोज के अनुसार, सभी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पतालों में श्रद्धालुओं को निःशुल्क परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सर्दी-खांसी, बुखार, सिरदर्द, जोड़ों और कमर का दर्द, त्वचा रोग, पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, अपच और मौसमी संक्रमण जैसी बीमारियों के लिए सबसे अधिक लोग इन केंद्रों का रुख कर रहे हैं। ठंड के मौसम और खुले वातावरण में रहने के कारण कल्पवासियों में जोड़ों के दर्द और सर्दी-जुकाम की समस्या आम रहती है, ऐसे में आयुर्वेदिक काढ़े, चूर्ण और तेलों से उन्हें विशेष राहत मिल रही है। कई श्रद्धालु एलोपैथिक दवाओं से परहेज करते हुए पूरी तरह आयुष पद्धति पर भरोसा जताते नजर आ रहे हैं।

मेला क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविरों की बढ़ती लोकप्रियता यह दर्शाती है कि लोगों का झुकाव अब प्राकृतिक और दुष्प्रभाव रहित उपचार की ओर तेजी से बढ़ रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि आयुर्वेद न केवल बीमारी के लक्षणों को दूर करता है, बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। यही कारण है कि कई श्रद्धालु यहां से केवल इलाज ही नहीं, बल्कि आहार-विहार और दिनचर्या से जुड़ी सलाह भी लेकर लौट रहे हैं, ताकि वे स्वस्थ जीवनशैली को अपनाकर लंबे समय तक निरोग रह सकें।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आयुर्वेदिक और अन्य आयुष पद्धतियों के प्रति लोगों का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। आयुष मंत्रालय के प्रयासों से आयुर्वेद केवल वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं रहा, बल्कि यह जीवनशैली से जुड़ा एक संपूर्ण उपचार बनता जा रहा है, जिसमें रोग निवारण के साथ-साथ स्वास्थ्य संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और बड़े धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया है। माघ मेला जैसे विशाल आयोजन में आयुर्वेद और होम्योपैथी के अस्पतालों में उमड़ती भीड़ इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोग अब त्वरित राहत के साथ-साथ स्थायी और सुरक्षित उपचार की तलाश में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह माघ मेला में श्रद्धालुओं का आयुर्वेद की ओर रुझान बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में यह चिकित्सा पद्धति न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवा का एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरेगी।

सोमनाथ मंदिर बना महिला सशक्तिकरण का आधुनिक मॉडल, 363 महिलाओं को सालाना 9 करोड़ का रोजगार

(जीएनएस)। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक श्री सोमनाथ मंदिर केवल आस्था और विश्वास का केंद्र ही नहीं रहा है, बल्कि समय के साथ यह सामाजिक बदलाव और महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। सदियों तक आक्रमणों, विध्वंस और पुनर्निर्माण के दौर से गुजरने वाला यह मंदिर आज आधुनिक भारत की उस सोच को भी प्रतिबिंबित करता है, जहां श्रद्धा के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व दिया जाता है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि धार्मिक संस्थान व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, तो वे समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली समावेशी और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। वर्तमान में ट्रस्ट के अंतर्गत कुल 906 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 262 महिलाएं विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक संदेश है कि मंदिर प्रबंधन महिलाओं को केवल सहायक भूमिका में नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया और सेवा व्यवस्था के अहम हिस्से के रूप में देखता है। मंदिर के प्रशासन, अनुशासन, स्वच्छता, प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सेवा से जुड़े अनेक कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने कार्य संस्कृति को अधिक संवेदनशील, व्यवस्थित और सेवा भाव से परिपूर्ण बनाया है।

विशेष उल्लेखनीय है मंदिर परिसर में स्थित पवित्र बिल्व वन, जिसे पूरी तरह महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहां 16 महिलाएं पर्यावरण संरक्षण, हरियाली के संवर्धन और परिसर की स्वच्छता की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। धार्मिक आस्था से जुड़े इस पवित्र स्थल पर प्रकृति और संस्कृति का जो सुंदर संतुलन दिखाई देता है, उसमें इन महिलाओं की मेहनत और समर्पण की बड़ी भूमिका है। यह व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं न केवल धार्मिक परंपराओं की संवाहक हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को भी पूरी कुशलता से निभा सकती हैं। मंदिर का भोजनालय भी महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण बन चुका है। यहां 30 महिलाएं प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को सेवा भाव और आत्मीयता के साथ भोजन परोसती हैं। यह कार्य केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव सेवा की उस परंपरा को जीवंत रखता है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इसी प्रकार प्रसाद वितरण जैसे अत्यंत पवित्र और विश्वास से जुड़े कार्य में 65 महिलाओं की भागीदारी यह दर्शाती है कि ट्रस्ट महिलाओं की ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी पर पूर्ण विश्वास करता है। श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव और भी विशेष बन जाता है, जब उन्हें सेवा देने वाली महिलाएं श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने कर्तव्य का पालन करती हैं।

कुल मिलाकर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से 363 महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। इन महिलाओं द्वारा सालाना लगभग 9 करोड़ रुपये की आय अर्जित की जा रही है। यह आय केवल आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवारों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। इस आर्थिक स्वावलंबन से महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और वे अपने परिवार के निर्णयों में पहले से कहीं अधिक सशक्त भूमिका निभा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के रूप में इसके दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं।

सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का यह मॉडल यह स्पष्ट करता है कि आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। मंदिर ने यह साबित किया है कि श्रद्धा को यदि सेवा और सशक्तिकरण से जोड़ा जाए, तो वह समाज को नई दिशा दे सकती है। महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास ने न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह मॉडल अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है।

आज श्री सोमनाथ मंदिर केवल घंटियों की गूंज और मंत्रोच्चार का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां से आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और स्वावलंबन का संदेश भी पूरे समाज में फैल रहा है। आस्था के इस पवित्र धाम ने यह दिखा दिया है कि सच्ची भक्ति वही है, जो मानव कल्याण, समानता और सामाजिक उत्थान के मार्ग पर समाज को आगे बढ़ाए।

रक्षा और ईवी उत्पादन का केंद्र बना उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींवः राजनाथ सिंह

(जीएनएस)। लखनऊ। देश की सामरिक शक्ति और औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब केवल देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं के लिए आवश्यक हथियार, गोला-बारूद, मिसाइल सिस्टम और युद्धपोतों से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ही तैयार होंगे। यह बदलाव आत्मनिर्भर भारत की सोच का ठोस प्रमाण है, जिसमें देश अपनी सुरक्षा जरूरतों को स्वयं पूरा करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है।

शुक्रवार को लखनऊ में अशोक लीलैंड के नए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र के उद्घाटन अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ स्थित ब्रह्मोस मिसाइल संयंत्र इस परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के लिए विदेशों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन आज वही तकनीक उत्तर प्रदेश में विकसित हो रही है। यह न केवल देश की सैन्य ताकत को मजबूत कर रही है, बल्कि युवाओं के लिए तकनीकी कौशल, रोजगार और नवाचार के नए द्वार भी खोल रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति ने इस अवसर को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में पिछले एक दशक में हुए बड़े बदलावों को रेखांकित करते हुए बताया कि वर्ष 2014 में देश का कुल रक्षा उत्पादन जहां लगभग 46 हजार करोड़ रुपये था, वहीं आज यह बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। इसी तरह रक्षा निर्यात में भी ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। पहले जहां रक्षा निर्यात एक हजार करोड़ रुपये से भी कम था, वहीं अब यह लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है।

रक्षा मंत्री ने अशोक लीलैंड के नए इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र को उत्तर प्रदेश पर उद्योग जगत के बढ़ते भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक फैक्ट्री की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बन चुका है। बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचा, औद्योगिक नीतियों में पारदर्शिता और विस्तृत सड़क नेटवर्क ने राज्य में बड़े निवेश को संभव बनाया है। लखनऊ जैसे शहर में अत्याधुनिक ईवी विनिर्माण इकाई का स्थापित होना इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है।

उन्होंने बताया कि करीब 70 एकड़ क्षेत्र में फैला यह उत्पादन केंद्र रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। जहां आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में वर्षों लग जाते हैं, वहीं इस संयंत्र का निर्माण मात्र 18 महीनों में पूरा किया गया। उत्पादन शुरू होने के बाद यहां हर महीने लगभग 2,500 इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किए जाएंगे। इससे न केवल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में इससे जुड़े सहायक उद्योगों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की संभावनाएं भी बनेंगी।

राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक, जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब उत्तर प्रदेश रोजगार, उद्योग, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा होगा। आज प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में बन रही है, जहां युवाओं को रोजगार की तलाश में बाहर जाने की मजबूरी नहीं है, बल्कि अवसर स्वयं उनके घर के पास उपलब्ध हो रहे हैं।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए विशेष ट्रेन से पहुंचे शिव भक्तों का वेरावल स्टेशन पर गर्मजोशी से स्वागत

- राजकोट, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद से ट्रेन के जरिए पहुंचे यात्रियों का ढोल-नगाड़ों, शहनाई और पारंपरिक गरबे से स्वागत
- प्रभास की धरती पर सूर्योदय की पहली किरण के साथ स्टेशन परिसर 'हर हर महादेव' और 'जय सोमनाथ' के नाद से गूंज उठा

(जीएनएस)। गांधीनगर : 8 से 11 जनवरी के दौरान आयोजित हो रहे भारत की आध्यात्मिक आस्था के प्रतीक 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शिव भक्त श्रद्धालुओं के लिए विशेष आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा जैसे शहरों से सोमनाथ आने को इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पवित्र सोमनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुलभ, सुरक्षित और अनुकूल यात्रा के लिए सरकार की ओर से योजनाबद्ध व्यवस्था की गई है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर वेरावल रेलवे स्टेशन पर विशेष स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। विभिन्न शहरों से ट्रेन के माध्यम से पहुंचे शिव भक्त श्रद्धालुओं का कुमकुम तिलक लगाकर तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर ढोल-नगाड़ों, शहनाई और पारंपरिक गरबे के जरिए हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। इस स्वागत कार्यक्रम में भक्तिभाव, आत्मीयता और सोमनाथ के प्रति अडिग आस्था का भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला।

प्रभास भूमि पर 9 जनवरी को सूर्योदय की पहली किरण के दौरान वेरावल स्टेशन परिसर यात्रियों के 'हर हर महादेव-जय सोमनाथ' के नाद से गूंज उठा।

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से स्टेशन से मंदिर तक जाने और वापस स्टेशन लौटने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और वडोदरा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन कर सकते हैं।

विशेष ट्रेन सुविधा के चलते शिव भक्तों को समय पर और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल रही है।

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए आवागमन, मार्गदर्शन और प्रबंधन सहित विभिन्न सुविधाओं का सुचारु रूप से संचालन किया जा रहा है।

श्रद्धालुओं को वेरावल रेलवे स्टेशन से सोमनाथ मंदिर तक पहुंचने में आसानी और सहुलियत हो, इसके लिए समन्वित आयोजन किया गया है।

यात्रियों की प्रतिक्रिया

इस बारे में तापी जिले के श्री अक्षय पंचाल ने कहा कि उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के कारण अच्छी तरह से दर्शन हो पाएगा। इस अवसर में सहभागी होने का उन्हें बहुत आनंद है।

सूरत निवासी श्री हेलीबेन राठोड़ ने कहा कि यहां ट्रेन में यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं मिलीं। स्टेशन से मंदिर तक जाने के लिए बस की व्यवस्था है, जिससे आसानी से दर्शन हो सकेगा।

बीसीसीएल का आईपीओ बाजार में उतरा, निवेशकों के लिए 13 जनवरी तक खुला रहेगा मौका

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कोल इंडिया की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने पूंजी बाजार में कदम रखते हुए अपना बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लॉन्च कर दिया है। कुल 1,071.11 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के साथ बीसीसीएल ने निवेशकों के लिए कोयला क्षेत्र की एक अहम सार्वजनिक पेशकश खोल दी है। यह इश्यू शुक्रवार से सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है और 13 जनवरी तक इसमें बोली लगाई जा सकेगी। इसके बाद 14 जनवरी को शेयरों का आवंटन किया जाएगा, 15 जनवरी को शेयर निवेशकों के डीमैट खातों में क्रेडिट होंगे और 16 जनवरी को इसके बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की संभावना है।

इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 21 से 23 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में 600 शेयर रखे गए हैं, यानी रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 12,600 रुपये के निवेश से शुरुआत करनी होगी, यदि वे निचले प्राइस बैंड पर आवेदन करते हैं। रिटेल निवेशकों को इस इश्यू में न्यूनतम एक लॉट और अधिकतम 14 लॉट तक बोली लगाने की अनुमति दी गई है। इस तरह अधिकतम रिटेल निवेश सीमा के भीतर रहते हुए निवेशक बड़ी हिस्सेदारी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आईपीओ के प्रति संस्थागत निवेशकों की रुचि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एंकर निवेशकों ने इश्यू खुलने से पहले ही 273.13 करोड़ रुपये का निवेश कर दिया। इनमें एलआईसी, निप्पन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड और बंधन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े और भरोसेमंद नाम शामिल हैं। यह निवेश बाजार में बीसीसीएल के प्रति विश्वास और दीर्घकालिक संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है।

शेयरों के आवंटन की बात करें तो इस इश्यू का 42.50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 29.75 प्रतिशत हिस्सा रिटेल निवेशकों, 12.75 प्रतिशत नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रखा गया है। कर्मचारियों के लिए 5 प्रतिशत और कंपनी के पुराने शेयरधारकों के लिए 10 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित किया गया है। इस संरचना से यह साफ है कि कंपनी ने संस्थागत निवेशकों के साथ-साथ आम निवेशकों और कर्मचारियों को भी संतुलित अवसर देने की कोशिश की है।

बीसीसीएल की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, हालांकि कुल मिलाकर कंपनी की आय और लाभ का स्तर मजबूत रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 664.78 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 में यह लाभ तेजी से बढ़कर 1,564.46 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 में इसमें कुछ गिरावट आई और शुद्ध लाभ 1,240.19 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी ने 123.88 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

राजस्व के मोर्चे पर भी बीसीसीएल का प्रदर्शन स्थिर और मजबूत रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का राजस्व 13,018.57 करोड़ रुपये था, जो अगले वर्ष बढ़कर 14,652.53 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व थोड़ा घटकर 14,401.63 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी ने 6,311.51 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है, जो सालाना आधार पर स्थिर मांग का संकेत देता है।

ईबीआईटीडीए के आंकड़ों में भी इसी तरह का उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। वित्त वर्ष 2022-23 में ईबीआईटीडीए 891.31 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,493.89 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 में यह थोड़ा घटकर 2,356.06 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ईबीआईटीडीए 459.93 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जो यह दर्शाता है कि परिचालन स्तर पर कंपनी अभी भी मुनाफे में है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में नवगठित शामलाजी तहसील में विकास उत्सव मनाया गया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र शामलाजी में मनाए जा रहे शामलाजी महोत्सव का समापन करते हुए अरवल्ली जिले को 168 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शामलाजी को नई तहसील घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला कार्यक्रम शामलाजी महोत्सव पूरे अरवल्ली जिले के लिए विकास उत्सव बन गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा अरवल्ली जिले के लिए पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत किए गए 1232 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों और वंचितों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विकास कार्यों में कभी धन की कमी नहीं पड़ने दी है।

- प्रसिद्ध यात्राधाम शामलाजी में शामलाजी महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति
- शामलाजी मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की
- अरवल्ली जिले को 168 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 'विकास भी, विरासत भी' मंत्र से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की दिव्यता एवं भव्यता को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास करने का दृष्टिकोण साकार किया है।

उन्होंने साफ कहा कि जनजातीय क्षेत्रों को आवास, अभ्यास (शिक्षा), आजीविका और आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर उप जिला अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन जनजातीय क्षेत्रों में 12 साइंस कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी और 11 मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से आदिवासी परिवारों की संतानों के लिए भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने की दिशा खुली है।

मुख्यमंत्री ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदिवासियों की परंपरागत कला, कौशल, पेशों और उत्पादनों को वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के माध्यम से प्रोत्साहन देने का भी आह्वान किया। मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व विकास किया है। विशेषकर, अरवल्ली जिले के आदिवासी क्षेत्रों में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। राज्य मंत्री श्री पी.सी. बरंडा ने कहा कि शामलाजी महोत्सव आदिवासी समुदाय की एकता, संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक है और इस वर्ष हजारों लोगों की भागदारी और कलाकारों के लोकसंगीत, नृत्य एवं भक्तिमय वातावरण से समुदाय की विरासत और अधिक मजबूत बनी है। उन्होंने कहा कि आज मिले विकास कार्यों और लोकार्पण से अरवल्ली के विकास को और गति मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क एवं भवन विभाग (राज्य) की 107.02 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, शिक्षा विभाग की 24.49 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, खेल विभाग की 19.9 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, सड़क एवं भवन विभाग (पंचायत) की 12.5 कोरड़ रुपए की परियोजनाओं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 3.46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

उन्होंने घुमंतू और विमुक्त जाति के परिवारों को भूखंड आवंटन के आदेश और किशन मिशन मंगलम समूह को कैश क्रेडिट सहायता वितरण किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका डामोर, सांसद श्रीमती शोभनाबेन बारैया, विधायक सर्वश्री भीखूसिंहजी परमार, धवलसिंह झाला, जिला प्रभारी सचिव श्री रूपवंत सिह, जिला कलेक्टर श्री प्रशस्ति पारिक, जिला विकास अधिकारी श्री दीपेश केडिया, जिला पुलिस अधीक्षक श्री मनोहरसिंह जाडेजा सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे।